aid on recurring basis or ad-hoc basis to Indian Council of World Affairs; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) and (b) Government funding to the Indian Council of World Affairs (ICWA) was discontinued in 1985. In pursuance of the recommendations of the Standing Committee of Parliament, the Government has decided that a high-powered committee should be constituted to look into the problems being faced by ICWA and suggest solutions. Any supervisory/advisory committee can only be constituted in pursuance of a request made by this organisation. The governing body of the Council is presently being persuaded to pass a resolution requesting the Government to set up such a high-powered committee. If and when this committee is established, the Government may provide funding on ad hoc/recurring basis. The quantum of such funding will have to be decided only at that time.

Violation of Human Rights in Pakistan Occupied Kashmir

5455. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have any account of the reported uprising of the people and violation of their human rights in Pakistan Occupied Kashmir, during the three years; and

(b) if so, what steps have been taken to inform the international community about the atrocities and violation of human rights perpetuated on the people of Pakistan Occupied Kashmir?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) and (b) Government are aware that people living in areas of Jammu & Kashmir, illegally occupied by Pakistan through aggression, are denied their democratic rights. According to avaiable information, recurring violence, sectarian strife and economic deprivation and backwardness seriously affect the rights and privileges of the people of these areas.

Government have and will contiue to apprise the international community of the true facts of the deplorable conditions prevailing in the Pakistan - Occupied Kashmir and the so-called 'Northern Areas'.

Pakistan's Declartaion about its Nuclear Programme

5456. SHRI V. NARAYANASWAMY:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Pakistan had declared that it was neither fair nor feasible for Islamabad to accept obligations and restraints regarding its nuclear programme;

(b) whether it is a fact that Pakistan was not being asked to sign the Nuclear Non-proliferatio Treaty (NPT) unilaterally and was also not being pressed to roll back its nuclear programmes; and

(c) if so, the reaction of Government and steps proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) and (b) Yes, Sir. Government has seen media reports quoting Pakistani leaders that Pakistan will not accept any unilateral restraints on its nuclear programme.

(c) The security situation of India remains constantly under review and Government will take all measures necessary to cope with any threat that may be posed to the security of the nation.

दोहरी पासपोर्ट प्रणाली को लागू करना

5457. **श्री अजीत जोगी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तथा भारत के अन्य निवासियों को एक से अधिक पासपोर्ट रखने अर्थात् भारतीय पासपोर्ट के साथ-साथ किसी अन्य देश का भी पासपोर्ट रखने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली कब से लागू की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ नियम बनाया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, नहीं। भारत किसी भी भारतीय राष्ट्रिक को एक ही समय किसी अन्य देश का पासपोर्ट रखने की अनुमति नहीं देता है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में हिन्दी के प्रचार पर व्यय की जाने वाली राशि

5458. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994–95 में विदेशों में हिन्दी के प्रचार हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा कितना बजटीय प्रावधान किया गया है;

(ख) हिन्दी के प्रचार के लिए भारतीय दूतावासों द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे है ; और

(ग) वर्ष 1993–94 के दौरान मंत्रालय द्वारा विभिन्न भारतीय दूतावासों को हिन्दी में कितने पत्र लिखे गए ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए वर्ष 1994–95 में 43 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया था ।

(ख) मंत्रालय की विदेश स्थित अपने मिशनों के माध्यम से हिन्दी के प्रचार-प्रसार की एक सुविचारित योजना है । इस योजना के एक भाग के रूप में हिन्दी शिक्षण से जुड़े स्थानीय शैक्षिक संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों इत्यादि को मानक हिन्दी साहित्य भेजा जाता है जिसमें भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, इतिहास, धर्म, दर्शन जैसे विभिन्न विषयों पर हिन्दी में लिखी पुस्तकें शामिल हैं । इन संस्थानों को हिन्दी की पाठ्य पुस्तकें शिक्षण सामग्री जैसेकि चार्ट, श्रव्य-दृश्य कैसेट, टाइपराईटर, कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर भी उपहार स्वरूप भेजे जाते है । मिशन अपनी ओर से स्थानीय संगठनों, भारतीय समुदाय आदि से निकट सम्पर्क बनाए रखते है और इस सामग्री को उपहार स्वरूप देकर उनकी हिन्दी भाषा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं । केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा में हिन्दी पढ़ने के लिए प्रदान की जा रही छात्रवृत्तियों के लिए विदेशी छात्रों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के उद्देश्य से वे स्थानीय विश्व विद्यालयों से भी सम्पर्क रखते हैं । हमारे कुछ मिशन उन स्थानीय छात्रों को, जो हिन्दी का ज्ञान रखते हैं, प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दी सम्मेलनों, साहित्यिक गतिविधियों, हिन्दी निबन्ध/वाद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य मिशन हिन्दी सीखने के इच्छुक स्थानीय लोगों के लिए कक्षाओं का आयो-